2019 लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद से मजदूरों ने उतारा अपना प्रत्याशी

फ़रीदाबाद, 16, अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद सीट से इंकलाबी मजदूर केंद्र ने अपने साथी संजय मौर्या को प्रत्याशी बनाया है। 16 अप्रैल को इंकलाबी मजदूर केंद्र के साथ वीनस वर्कर्स यूनियन, वं औद्योगिक ठेका मजदूर यूनियन और सैकड़ों महिला एवं पुरुष मजदूर साथियों व के समाजिक कार्य कर्ताओं ने लघु सचिवालय सेक्टर 12, पहुंच कर अपने प्रत्याशी का पर्चा दाखिल किया।

संजय मौर्या ने कहा कि वह इस चुनाव के माध्यम से आम जनता के मुद्दों को पटल पर लाने व देश को देशी विदेशी पूंजी के लुट से बचाने की लड़ाई को जनता की लड़ाई बनाना चाहता है । उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती भूख, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी का कारण एक मात्र मुनाफे की लुट पर टिकी यह पूंजीवादी व्यवस्था है जिसके लिए हमारे शासकों चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, निजीकरण की नीतियां ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है ।

ऐसे में शिक्षा के नाम पर प्राईवेट स्कूलों कालेजों के नाम की दुकानों में लुट का धंधा हमारे नेताओं मंत्रीओं के मेहरबानी से ही चरम पर है । तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य के नाम पर लाशों से भी पैसा वसूलने का धंधा अस्पताल नामक कत्ल खानों में बे रोक टोक चल रहा है ।

जनता के पैसे से खड़ी की गई सरकारी संस्थानों को हमारे नेता अपने चहेते कार्पोरेटस को लुटा रहे हैं। देश के कार्पोरेटीकरण से बढती अमीरी गरीबी के बीच खाई ने आम जनता के भीतर असंतोष व आक्रोश को पैदा किया है । जिससे पूंजीपतियों नेताओं के लुट पर टिकी इस

व्यवस्था को बचाने के लिए ही मोदी सरकार ने जनता को मन्दिर, मस्जिद, जाति-धर्म, हिन्दू-मुस्लिम, शमशान-कब्रिस्तान,अली- बजरंगबली, अंधराष्ट्रवाद जैसे फर्जी मुद्दों को उछाल कर जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है जिससे अडानी, अम्बानी, अमेरिकी, जापानी सभी देशी विदेशी कंपनियों द्वारा देश की लुट को बदस्तूर जारी रखा जा सके । परन्तु इनके फासीवादी एजेंडे को भारत का मजदूर किसान छात्र नौजवान देर सबेर समझ जायेगा जरुर और हमारे आम जनता के नारे को अपनाते हुए हमारी सच्ची लड़ाई के साथ खड़ा होगा क्योंकि हमारी लड़ाई भुख, गरीबी के खिलाफ है । हमारी लड़ाई अशिक्षा, बेरोजगारी के खिलाफ है । हमारी लड़ाई निजीकरण के भी खिलाफ है। हम ठेकेदारी प्रथा खत्म कर स्थाई रोजगार चाहते हैं। हम महिलाओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ हैं । हमरा संघर्ष महिला हिंसा को बढ़ावा देने वाली पूंजीवादी संस्कृति के खिलाफ है ।

हम लाखों करोड़ों मजदूरों को मात्र जिन्दा भर रहने के शर्तें पर कारखानों खदानों में खाटाऐ जाने के खिलाफ हैं हम लड़ इस लिए भी रहे हैं कि फरीदाबाद के साथ साथ देश भर के मजदूरों को सम्मान जनक जीवन जीने लायक तनख्वाह स्थाई रोजगार मिल सके ।बेरोजगारों को रोजगार, बीमारों को सही समय पर सही इलाज और हर बच्चे को शिक्षा मिल सके । इसके लिए जरूरत है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संघर्ष किया जाऐ । हमारा संघर्ष तो शिक्षा मित्र, भोजन माताएं, आशा वर्कर्स को सरकार द्वारा नाममात्र के मानदेय पर कराए जा रहे बेगार को खत्म कर सम्मान जनक वेतन तथा उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने का संघर्ष है ।

किसानों को पूंजीवादी बाजार के चंगुल से मुक्त कराकर उनके तबाही-बर्बादी, आत्महत्याओं को रोकने के लिए पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष है। भगतसिंह के बिचारों को मानें तो उपरोक्त समस्याओं का समाधान और आम जनता की मुक्ति पूंजीवादी जनतंत्र में नहीं बल्कि समाजवादी जनतंत्र में ही सम्भव है ।

ईएसआई में रैबीज़ के टीके नहीं हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) मज़दूरों के वेतन का साढे छह प्रतिशत लूट कर अपना खजाना भरने वाले ईएसआई कार्पोरेशन के तमाम अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में रैबीज़ के टीके उपलब्ध नहीं है। कुत्ता काटे का शिकार मज़दूर जब इन अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में जाता है तो उसे कहा जाता है कि वह बाज़ार से टीका खरीद लाये तो अस्पताल वाले लगा देंगे। विदित है कि रैबीज़ के एक इंजेक्शन की कीमत 400 रुपये है और ऐसे चार इंजेक्शन लगते हैं। जब वह सवाल जवाब करता है तो उसे समझाया जाता है कि फ़िलहाल वह खरीद लाये बाद में ईएसआई रिफ़ंड कर देगा। मात्र 12000 मासिक कमाने वाला मज़दूर जो इसमें से साढे छह प्रतिशत पहले ही ईएसआई को दे चुका है वह 1600 रुपये कहां से खर्च करेगा इस महंगाई के जमाने में? दूसरे जब ईएसआई ने रिफ़ंड ही करना है तो वह खुद क्यों नहीं खरीद कर रखते?

विदित है कि ईएसआई से रिफ़ंड लेना कोई आसान काम नहीं। तरह-तरह की औपचारिकतायें पूरी करने के बाद डिस्पेंसरी व लोकल ऑफ़िस के चक्कर काटने में जो उसकी दिहाड़ियां बर्बाद होगी, उससे बचने के लिये वह इस चक्कर में नहीं पड़ता और बिना इंजेक्शन के ही भगवान भरोसे रह जाता है।

यह मामला कोई अकेले इसी शहर का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का है। मामले की गंभीरता को समझते हुए इस संवाददाता ने हरियाणा ईएसआई हैल्थ केयर के डायरेक्टर डॉ. अनिल मलिक को चंडीगढ 9216165611 पर फ़ोन लगाया। उन्होंने बताया कि एक-दो माह पहले उन्हें यह बात बताई गयी थी तो उन्होंने स्थानीय अस्पतालों को स्वयं खरीद कर मरीज़ों को इंजेक्शन लगाने को कहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि 6-7 माह से समाप्त इंजेक्शनों के बारे में उन्हें केवल एक-दो माह पूर्व ही पता चला। उन्होंने इस संवाददाता को धन्यवाद दिया कि अच्छा किया जो उन्हें बता दिया कि स्थानीय अस्पताल वाले स्वयं वेक्सीन नहीं खरीद रहे हैं।

असल में यह सब डायरेक्टर मलिक की नौटंकी है। जिस डायरेक्टर को यह नहीं पता कि उसके राज्य भर के अस्पतालों में रैबीज़ के वेक्सीन बीते 6-7 माह से नहीं हैं, उसे पद पर रहने का कोई हक नहीं है। यह सब तब हो रहा है जब धन की कोई कमी नहीं है। जिस स्थानीय खरीद की बात डॉ. मलिक ने कही उस से भद्दा मज़ाक कोई हो नहीं सकता क्योंकि अस्पताल के एमएस की पावर केवल 2000 रुपये तक की दवायें खरीदने की है। यानी ऊंट के मुंह में जीरे के समान। इस रकम से तो केवल एक ही मरीज के लिये वेक्सीन खरीदा जा सकता है।

दरअसल इसके लिये अकेले डॉ. मलिक को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। असल उत्तरदायी तो वह खट्टर सरकार है जिसने उन्हें वहां बैठा रखा है। दूसरे, स्थानीय राजनेता जो पूरी बेशर्मी के साथ वोट मांगने तो निकले हैं लेकिन उनके द्वारा संचालित अस्पतालों का यह हाल है। केबल रैबीज़ वैक्सीन की बात नहीं और भी बहुत सी दवायें अस्पताल में नहीं हैं। अल्ट्रासाऊंड मशीन बीते छह साल से कंडम हुई पड़ी है, नई खरीदने की चर्चा तो हर साल होती है लेकिन खरीदी नहीं जाती और बजट लैप्स हो जाता है। यह हरामखोरी नहीं तो क्या है। अस्पताल में न तो कोई सर्जन है न कोई हड्डियों का डॉक्टर, इसके चलते ऑपरेशन थियेटर को बरसों से ताला लगा पड़ा है।

सुधी पाठकों ने 'मज़दूर मोर्चा' में कई बार पढा होगा कि राज्य में ईएसआई स्वास्थ्य सेवायें चलाने का पूरा जिम्मा राज्य सरकार का है। इसके लिये तमाम तरह की भर्तियां व खरीदारी राज्य सरकार का ईएसआई हैल्थ केयर निदेशालय करता है। इसके लिये बजट भी स्वयं उसे ही बनाना होता है। हरियाणा में ईएसआई कवर्ड मज़दूरों की संख्या को देखते हुए निदेशालय को जो बजट कम से कम 1200 करोड़ का बनाना चाहिये, उसकी जगह ये बनाते हैं मात्र 162 करोड़ का और उसे भी पूरा खर्च नहीं करते। यदि 1200 करोड़ का बजट बनता है तो राज्य सरकार को मात्र 150 करोड़ खर्च करने पड़ते। लेकिन अब ईएसआई कार्पोरेशन ने यह शर्त भी हटा दी है यानी पूरा बजट कार्पोरेशन ही अदा करेगी। इसके बावजूद यह निकम्मी एवं जन विरोधी सरकार पूरा बजट नहीं बना रही।

बजट के अभाव में न तो राज्य के किसी ईएसआई अस्पताल व डिस्पेंसरी में न तो पर्याप्त डॉक्टर व स्टाफ़ हैं और न ही दवायें व उपकरण आदि। इनके अभाव में ठगा सा महसूस करने वाला मज़दूर वर्ग मन मसोस कर रह जाता है तथा इलाज के लिये झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में फ़ंसा रहता है।

खट्टर सरकार की शह पर पार्क में अवैध कब्जा

उक्त चित्र सैक्टर नौ के उस पार्क में हो रहे अवैध कब्जे का है जिसके एक सिरे पर डीसी मॉडल स्कूल व दूसरे सिरे पर चर्च बना है। यह अवैध कब्जा चर्च के बिल्कुल बगल में हो रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 'हूडा' ने एक एकड़ भूखंड को किसी भी नाम अलॉट नहीं किया है। इस बाबत सैक्टर नौ के निवासियों ने जनवरी 2019 में आरटीआई द्वारा 'हूडा' अधिकारियों से जानकारी मांगी थी जिसका खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया, जाहिर है इसमें अवश्य ही कोई गोलमाल है।

जैसा कि चित्र से विदित है काफी मोटे सरियों के पिलर बनाये जा रहे हैं जिससे लगता है कि योजना किसी बहुमंजिला इमारत के निर्माण की है। इसबाबत ताजा स्थिति जानने हेतु इस संवाददाता ने 'हूडा' के सम्पदा अधिकारी भारत भूषण गोगिया को उनके मोबाईल नं 9729322277 पर कई बार बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।

रिश्ते ही रिश्ते

माँ झण्डे वाली मैरिज ब्यूरो

OFFICE : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD

CONTACT : ANSHU DUA

(M) : 9990589008, 7982962823, 9891124022

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207